Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

दिसंबर 2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- ➢ राज्य सरकार का पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला 3
- ➢ शिवपुरी की मुस्कान शेख ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते चार स्वर्ण पदक 3
- ➢ कान्हा टाइगर रिज़र्व में जंगली भैंसें बसाएगी सरकार 4
- ➢ 'अनुगूँज' का स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ 4
- ➢ कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से जल्द आएंगे 12 नए चीते, एमओयू को मिली मंजूरी 5
- ➢ पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वैलनेस केंद्र भोपाल में शुरू 5
- ➢ आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन की निगरानी समिति का पुनर्गठन 6
- ➢ सुपोषित मध्य प्रदेश के लिये प्रोजेक्ट 'समग्र' प्रारंभ 6
- ➢ विश्व विख्यात साँची बनेगा सोलर सिटी 7
- ➢ भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले 'मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक' का शुभारंभ 7
- ➢ इंदौर नगर निगम 60 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिये जारी करेगा ग्रीन बांड 8
- ➢ शूटर ऐश्वर्य प्रताप, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर की तिकड़ी ने जीता टीम इवेंट में स्वर्ण 8
- ➢ राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में एस. एल. आर. दुबे ने जीता गोल्ड मेडल 9
- ➢ संजय कुमार मिश्रा होंगे झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस 9
- ➢ मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 9
- ➢ मोहसा-बावई में औद्योगिक विकास के लिये भूमि आवंटित की गई 10
- ➢ मध्य प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 का अनुसमर्थन 11
- ➢ मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर से 5G नेटवर्क की शुरुआत 12
- ➢ मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने लॉन्च किया मुक्ता ब्रांड घी 13
- ➢ मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने लॉन्च किया मुक्ता ब्रांड घी 13
- ➢ मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 14
- ➢ स्कूली शिक्षा में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य 15
- ➢ मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य 15
- ➢ 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 प्रारंभ 15
- ➢ स्टेट हैंडलूम एक्सपो में डिजाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को मिले पुरस्कार 16
- ➢ लोक निर्माण विभाग में 'क्वालिटी कंट्रोल सेल' गठित 16
- ➢ संस्कृति विभाग के राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों की घोषणा 17
- ➢ 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ समापन 17
- ➢ मध्य प्रदेश ट्रांसको के लोड डिस्पेच सेंटर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 18
- ➢ मुख्यमंत्री ने सीहोर ज़िले में किया सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण 18
- ➢ अंतर्राष्ट्रीय वन मेला: वन मंत्री डॉ. शाह ने वन मेले में वितरित किये पुरस्कार 19
- ➢ स्काई डाईविंग फेस्टिवल 20
- ➢ पीबीडी और जीआईएस के लिये इंदौर में होम-स्टे योजना 20
- ➢ महानगरों की तर्ज पर तैयार होगा राहतगढ़ का अत्याधुनिक बस स्टैंड 21

नोट :

The Vision

मध्य प्रदेश

राज्य सरकार का पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 6वें और 7वें वेतनमान पर एक अक्टूबर 2022 से पेशन पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई राशि नवंबर 2022 से देय होगी। वित्त विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- छठवें वेतनमान में 12 प्रतिशत की वृद्धि के बाद महंगाई राहत की दर अब 201 प्रतिशत हो गई है। सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि से महंगाई राहत दर 33 प्रतिशत हो गई है।
- आदेश जारी होने के पहले 6वें वेतनमान में मूल पेंशन एवं परिवार पेंशन पर 189 प्रतिशत की दर एवं 7वें वेतनमान में 28 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही थी। आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरित्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।
- महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर भी देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किये गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के आदेश अनुसार देय होगी।
- यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो पति-पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।
- यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थान, मंडल, निगम आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
- संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं में नमूना जाँच करने तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गए हैं। सभी पेंशन संवितरणकर्त्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।

शिवपुरी की मुस्कान शेख ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते चार स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले की मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में चार स्वर्ण पदक जीतकर मध्य प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है।

प्रमुख बिंदु

- मुस्कान ने एस्कॉट लिफ्टिंग में 105 किलो, बेंच प्रेस में 57.5 किलो और डेड लिफ्टिंग में 120 किलो भार उठाया और तीनों कैटेगरी में अव्वल आने के बाद उसे टोटल वेट काउंट के लिये भी स्वर्ण पदक मिला।

नोट :

- शिवपुरी ज़िले के छोटे से गाँव मझेरा की रहने वाली 18 वर्षीय मुस्कान शेख 2016 से पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले मुस्कान हैंड बॉल में अपनी किस्मत आजमा चुकी है लेकिन गाँव में तैयारियों में समस्या आने के बाद उनका झुकाव वेट लिफ्टिंग की ओर हो गया।
- मुस्कान ने 2016 में पहली बार स्टेज हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसके बाद साल 2017-18-19 में वह नेशनल खेल चुकी हैं। उसके पिता दारा मोहम्मद पोल्ट्री फॉर्म का व्यवसाय करते हैं।

कान्हा टाइगर रिज़र्व में जंगली भैंसें बसाएगी सरकार

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के पीसीसीएफ वन्यप्राणी, जे.एस. चौहान ने कहा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसें बसाने की तैयारी है। वन विभाग असम सरकार को पत्र लिखकर जंगली भैंसों की मांग करेगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आज से 40 साल पहले जंगली भैंसें पाए जाते थे। धीरे-धीरे वे विलुप्त हो गए। अब राज्य सरकार एक बार फिर प्रदेश के जंगल को जंगली भैंसों से आबाद करने का प्रयास कर रही है।
- एशियाई जंगली भैंसों की संख्या वर्तमान में चार हजार से भी कम रह गई है। एक सदी पहले तक पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले जंगली भैंसें आज केवल भारत, नेपाल, बर्मा और थाईलैंड में ही पाए जाते हैं।
- भारत में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं। मध्य भारत में ये छत्तीसगढ़ में गरियाबंद ज़िले के सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व और बीजापुर ज़िले के कुटरु में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।
- जंगली भैंसों की एक प्रजाति, जिसके मस्तक पर सफेद निशान होता है, पहले मध्य प्रदेश के वनों में भी पाई जाती थी, लेकिन अब विलुप्त है।
- मादा जंगली भैंस अपने जीवन काल में पाँच बच्चों को जन्म देती है। इनकी जीवन अवधि नौ साल की होती है। आम तौर पर मादा जंगली भैंसे और उनके बच्चे झुंड बनाकर रहती हैं और नर झुंड से अलग रहते हैं। लेकिन यदि झुंड की कोई मादा गर्भ धारण के लिये तैयार होती है तो सबसे ताकतवर नर उसके पास किसी और नर को नहीं आने देता। यह नर आम तौर पर झुंड के आसपास ही बना रहता है।
- नर बच्चे दो साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। जंगली भैंसा का जन्म अक्सर बारिश के मौसम के अंत में होता है। यदि किसी बच्चे की माँ मर जाए तो दूसरी मादाएँ उसे अपना लेती हैं।
- जंगली भैंसों को सबसे बड़ा खतरा पालतू मवेशियों की संक्रमित बीमारियों से है, इनमें प्रमुख बीमारी फुट एंड माउथ है। रिडंर्पेस्ट नाम की बीमारी ने एक समय इनकी संख्या में बहुत कमी ला दी थी।

'अनुगूँज' का स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, भोपाल में 'अनुगूँज' के चतुर्थ संस्करण का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 'कला से समृद्ध शिक्षा' के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाले शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम 'अनुगूँज' का आयोजन 5 दिसंबर तक किया जाएगा।
- 'अनुगूँज' मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का वैश्विक शिक्षा प्रणाली STEAM (साइंस, टैक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्टस और मैथेमेटिक्स) की दिशा में 'कला से समृद्ध शिक्षा' का अभिनव कार्यक्रम है। अब अनुगूँज के कार्यक्रम अन्य संभागों में भी आयोजित किये जा रहे हैं। इन संभागों की कुछ मोहक प्रस्तुतियाँ राजधानी भोपाल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शामिल हैं।

नोट :

- मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने कहा कि भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय 'अनुगूँज' के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के विद्यार्थी प्रतिभागिता कर रहे हैं। 'अनुगूँज' तीन प्रमुख भागों रंगकार, धनक और सृजन के अंतर्गत संपादित किया जा रहा है।
- अनुगूँज' विद्यार्थियों को 'कला के साथ शिक्षा' के संदर्भ में बड़े उत्साह के साथ कलाओं की बारीकियाँ सीखने का अवसर प्रदान करता है।
- केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये मध्य प्रदेश को उत्तर पूर्वी राज्यों, मणिपुर एवं नागालैंड के साथ समूहबद्ध किया गया है, जिससे अंतर्राज्यीय संस्कृति, कलाओं एवं शैलियों को जानने का अवसर मिले। इस तारतम्य में अनुगूँज 2022 में इन राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी।

कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से जल्द आएंगे 12 नए चीते, एमओयू को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

4 दिसंबर, 2022 को श्योपुर ज़िले के राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य के डीएफओ प्रकाश शर्मा ने मीडिया को बताया कि कूनो नेशनल पार्क में जल्द ही दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के वन और पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रीसी ने प्रोजेक्ट चीता के लिये भारत के साथ एमओयू को मंज़ूरी दे दी है। दस्तावेज़ अब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के पास है।

प्रमुख बिंदु

- डीएफओ प्रकाश शर्मा ने बताया कि भारत आने के लिये दक्षिण अफ्रीका में बीते साढ़े तीन माह से 12 चीतों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इन चीतों को आगामी 15 दिसंबर तक भारत के श्योपुर कूनो में लाया जा सकता है। पार्क में नए आने वाले चीतों के लिये आठ नए बाड़े भी बनाकर तैयार किये गए हैं।
- गौरतलब है कि जुलाई 2022 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका से चीता प्रोजेक्ट के लिये 12 चीतों को दिये जाने का आग्रह किया था। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से एक साथ चीते लाकर भारत में बसाए जाने थे।
- चीतों के चयन से लेकर इनको क्वारंटीन करने तक की तैयारी नामीबिया के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भी उसी समय पूरी कर ली गई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से चीता लाने का एमओयू साइन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से नामीबिया से आठ चीते भारत आ गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में चिह्नित किये गए 12 चीते क्वारंटीन बाड़ों में ही बंद रह गए।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, 2022 को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को छोड़ा था।

पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वैलनेस केंद्र भोपाल में शुरू

चर्चा में क्यों?

6 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वैलनेस केंद्र तथा रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज परिसर में बने 50 बिस्तरों वाले पंचकर्म एवं वैलनेस सेंटर में केरल के थेरेपिस्ट पंचकर्म करेंगे। इसके लिये कॉलेज प्रबंधन ने केरल से थेरेपिस्ट नियुक्त किये हैं।
- आयुष संचालनालय के अंतर्गत विकसित पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र में स्पेशलाइज्ड पंचकर्म चिकित्सा, संधि-गत एवं स्पाइन रोग चिकित्सा, जीवन शैली जन्य रोग निवारण, एडवांस न्यूरो रिहेबिलिटेशन, वृद्धावस्था जन्य रोग चिकित्सा, गर्भिणी एवं सूतिकाचार्य, बाल रोग, कायाकल्प, त्वचा एवं सौंदर्य सलाह, तनाव प्रबंधन, प्रकृति परीक्षा, नाड़ी परीक्षा जैसी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- केंद्र में अंतरंग रोगी विभाग, सुपर डीलक्स रूम, डीलक्स रूम और सेमी प्राइवेट सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जकूजी सोना बाथ, स्टीम चेंबर, योग, ध्यान एवं आयुर्वेद आहार, केरलीय पंचकर्म, अभ्यंगम, शिरोधारा जैसे उपचार की भी व्यवस्था है।

नोट :

- आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो काँवरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लागू 'वैद्य आपके द्वार' योजना, धनवंतरि ट्रेनिंग के रूप में हुए नवाचार, देवारण्य योजना तथा योग से निरोग कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आयुष के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
- आयुष राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य टॉस्क-फोर्स का गठन किया गया है। टॉस्क-फोर्स में देश के जाने-माने शिक्षाविद् एवं शोध विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। टॉस्क-फोर्स के सुझाव से आयुर्वेद के क्षेत्र में नवीन शोध के लिये अधो-संरचनात्मक विकास, कार्य पद्धति विकसित करने में सहयोग मिलेगा। प्रदेश के सात महाविद्यालयों में भी शोध केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन की निगरानी समिति का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व में (2016 में) गठित समिति का पुनर्गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- समिति में प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, स्कूल शिक्षा, महिला-बाल विकास, जनगणना निदेशक, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, राज्य नोडल अधिकारी ई-गवर्नेंस, उप-महानिदेशक यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सदस्य और प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य सचिव होंगे।
- भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं नागरिकों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिये पुनर्गठित समिति द्वारा आधार नामांकन और अद्यतनीकरण पारिस्थितिकी-तंत्र के कार्यान्वयन की निगरानी, आधार पहचान प्लेटफॉर्म के उपयोग की समीक्षा एवं नागरिक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी के कार्य किये जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त समिति द्वारा आधार पारिस्थितिकी-तंत्र के भागीदार की सूचना सुरक्षा और गोपनीयता प्रथाओं की समीक्षा, ज़िला स्तरीय आधार निगरानी समितियों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और राज्य सरकार के पोर्टल की कार्य-प्रणाली की निगरानी के कार्य किये जाएंगे।

सुपोषित मध्य प्रदेश के लिये प्रोजेक्ट 'समग्र' प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2022 को प्रदेश में कुपोषण के स्तर को समाप्त करने तथा सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राज्य सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) के मध्य प्रोजेक्ट 'समग्र' के क्रियान्वयन के लिये एमओयू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- अपर मुख्य सचिव महिला-बाल विकास अशोक शाह की उपस्थिति में संचालक महिला-बाल विकास डॉ. राम राव भोंसले और निदेशक पब्लिक हेल्थ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन डॉ. महेश श्रीवास ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- अपर मुख्य सचिव अशोक शाह ने कहा कि प्रोजेक्ट 'समग्र' का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, सीखने की क्षमता में वृद्धि तथा महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी आय में वृद्धि के अवसर बनाना है।
- संचालक महिला-बाल विकास डॉ. भोंसले ने बताया कि प्रोजेक्ट समग्र में विदिशा ज़िले के ग्यारसपुर ब्लॉक में ज़ीरो से 6 वर्ष के लगभग 10 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट ग्यारसपुर ब्लॉक की 229 आँगनवाड़ी, 184 स्व-सहायता समूह और 112 एसएचजी रसोई तक पहुँचेगा।
- उन्होंने बताया कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन प्रोजेक्ट समग्र आँगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये टीएचआर और पका हुआ गर्म भोजन, बीमार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण घर आधारित देखभाल और पोषण परामर्श प्रदान करने के लिये फ्रंटलाइन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कौशलवर्धन करेगा।

नोट :

- इसके अतिरिक्त अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के समय पर रेफरल के लिये लिंकेज को मजबूत करने और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये स्कूल की तैयारी सुनिश्चित करने के साथ ही आँगनवाड़ी केंद्रों को आवश्यकता आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करने संबंधी कार्य भी करेगा।
- एआईएफ के कंट्री डायरेक्टर मेथ्यू जोसेफ ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला-बाल विकास विभाग के साथ इस साझेदारी से महिलाओं, बच्चों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट समग्र की सफलता का आकलन करने के लिये एंड लाइन सर्वे करवाकर तथा प्रगति का नियमित मूल्यांकन और आवधिक प्रक्रिया प्रतिवेदन तैयार कर समय-समय पर राज्य के साथ साझा किया जाएगा।

विश्व विख्यात साँची बनेगा सोलर सिटी

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रायसेन ज़िले में स्थित एक छोटा सा कस्बा साँची, जो स्तूपों और बौद्ध तीर्थ स्थल के लिये विश्वविख्यात है, अब जल्द ही देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। साँची में सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सोलर सिटी बनने से बिजली आपूर्ति में आत्म-निर्भर होने के साथ ही साँची की अगले पाँच वर्षों की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा से सुनिश्चित होगी। साथ ही सौर स्ट्रीट लाइट, गार्डन लाइट, स्टड लाइट, हाई-मास्ट लाइट, सौर पेयजल कियोस्क, लोक परिवहन के लिये बैटरी चालित ई-रिक्शा, चार्जिंग स्टेशन, अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्र विंड टर्बाइन एवं पिजो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स स्थापित किये जाएंगे।
- इसी क्रम में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा साँची में ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा देने एवं सोलर रूफटॉप लगाने के लिये आम जन को प्रेरित करने के उद्देश्य से 12 से 18 दिसंबर तक साँची में सोलर रूफटॉप नोडल एजेंसियों के माध्यम से जन-जागृति शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में सोलर लगाने के लाभ एवं सोलर रूफटॉप लगाने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा।
- सोलर रूफटाप : लाभ एक नज़र में
  - अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत या खुली जगह पर सोलर पैनल लगाएँ और बिजली पर होने वाले खर्च को बचाएँ।
  - सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा।
  - इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।
  - एक किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल के लिये लगभग 100 स्क्वायर फुट जगह की ज़रूरत होगी।
  - 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा मिलेगी।
- सोलर प्लांट लगाने पर खर्च: ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 किलोवाट तक (10 किलोवाट प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।

भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले 'मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले 'मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि एक ही स्थान पर स्त्री रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, शिशु रोग सहित अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक शुरू किये जा रहे हैं।

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा है कि भोपाल नगर में 32 मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक शुरू किये जाएंगे। पॉली क्लीनिक में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ उपचार के लिये उपलब्ध रहेंगे। साथ ही विभिन्न जाँच और दवाइयाँ नि:शुल्क उपलब्ध होंगी।
- मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि हाल ही में मंत्रि-परिषद द्वारा 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएँ शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विद्यार्थियों को मातृभाषा हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा दी है।
- चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार कर गोविंदपुरा क्षेत्र में पाली क्लीनिक शुरू की जा रही है। पॉली क्लीनिक से ईएसआई को भी जोड़ेंगे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ होगा।

इंदौर नगर निगम 60 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिये जारी करेगा ग्रीन बांड

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जानकारी दी कि नगर पालिका इंदौर जलूद पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिये ग्रीन बांड जारी करेगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि नगर निगम ग्रीन बांड से 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।
- ग्रीन बांड जारी करने के प्रस्ताव पर नगर निगम परिषद् इंदौर की स्वीकृति के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। बांड राशि की वापसी नगर निगम इंदौर अपने स्तर से करेगा। शासन इसके लिये अलग से कोई वित्तीय सहायता नहीं देगा।

शूटर ऐश्वर्य प्रताप, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर की तिकड़ी ने जीता टीम इवेंट में स्वर्ण

चर्चा में क्यों?

9 दिसंबर, 2022 को केरल के तिरूवनंतपुरम के वट्टीयूरकाव शूटिंग रेंज में चल रही 65वीं राष्ट्रीय रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर की तिकड़ी ने 50 मीटर रायफल सीनियर मेंस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा 50 मीटर रायफल थ्री-पोजिशन सीनियर मेंस सिविलियन टीम इवेंट में अकादमी के अमित कुमार, हर्षित बिंजवा और याकूब सिद्दीकी ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया।
- टीम इवेंट का तीसरा स्वर्ण 50 मीटर थ्री-पोजिशन जूनियर मेंस में अकादमी के शूटर्स अविनाश यादव, अमित सिंगरोले और आदर्श ने जीता। इसी कड़ी में 50 मीटर थ्री-पोजिशन जूनियर मेंस सिविलियन टीम इवेंट में अकादमी के समीर उल्ला खान, अमित सिंगरोले और आदर्श तिवारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
- चैंपियनशिप में अकादमी के हर्षित बिंजवा ने मेंस एकल सिविलियन इवेंट में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। अकादमी के ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर सीनियर मेंस एकल मुकाबले में काँस्य पदक हासिल किया।
- वहीं नई दिल्ली में चल रही 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के अर्जित सिंह यादव ने स्वर्ण, अर्जुन ठाकुर ने रजत और ऋतुराज बुंदेला ने काँस्य पदक हासिल किया।
- सीनियर टीम इवेंट में अकादमी के अर्जुन ठाकुर, अर्जित सिंह और ऋतुराज बुंदेला की तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया।
- जूनियर टीम इवेंट में अर्जित सिंह यादव, ऋतुराज बुंदेला और अतुल सिंह राजावत ने रजत पदक हासिल किया। जूनियर महिला स्कीट इवेंट में अकादमी के वंशिका तिवारी, काजल सिंह और शिवानी ने काँस्य पदक हासिल किया।

- इसी प्रकार भोपाल के बिसनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में चल रही 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग पिस्ट्रल चैंपियनशिप में हरियाणा के अनीश भनवाला ने राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया। अनीश ने 588 प्वाइंटस् का अपना ही पुराना रिकार्ड तोड़ कर 590 प्वाइंटस् अर्जित कर नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया।
- उल्लेखनीय है कि अनीश भनवाला 2018 में 15 वर्ष की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता थे। वे 5 वर्षों से जूनियर नेशनल चैंपियन भी हैं।

राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में एस. एल. आर. दुबे ने जीता गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को स्टेट मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा सीआईएसएफ ग्राउंड भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में वित्त विभाग में पदस्थ एस.एल.आर. दुबे ने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि एस.एल.आर. दुबे ने गत माह उज्जैन में हुई राज्य स्तरीय गेम्स प्रतियोगिता में लॉन टेनिस एवं 100 मीटर दौड़ में गोल्ड तथा लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता था।
- अखिल भारतीय राष्ट्रीय लॉन टेनिस मध्य प्रदेश की टीम में भी दुबे का चयन हुआ है। इस टीम में ओपन केटेगरी से 4 एवं 45 प्लस केटेगरी से 3 खिलाड़ी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिये चयन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 12 से 17 दिसंबर तक हरियाणा के पंचकुला में होने जा रही है।
- दुबे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। वे अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर बिना देखे सबसे तेज सुंदरकांड पढ़ने का वर्ष 2018 में रिकॉर्ड बना चुके हैं। हनुमान चालीसा डेढ़ मिनट और शिव तांडव 2 मिनट में कह देते है। उनके लिये नंबर्स के स्क्वायर एवं रूट बताना सामान्य बात है।

संजय कुमार मिश्रा होंगे झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने संजय कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है, जिसकी स्वीकृति के बाद संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे।

प्रमुख बिंदु

- झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन 19 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में पद खाली न रहे इसलिये सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे।
- गौरतलब है कि वर्ष 2009 में संजय कुमार मिश्रा को उड़ीसा हाई कोर्ट का जज बनाया गया था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर उत्तराखंड हाई कोर्ट कर दिया गया था। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं।
- विदित है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट सहित तीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति की है।

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 का अनुमोदन सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 का मंत्रिपरिषद् नें अनुमोदन किया। स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल, अभ्युदय विश्वविद्यालय, खरगोन एवं अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालयों की स्थापना विधेयक के माध्यम से किये जाने के संबंध में प्रस्तुत द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
- रीवा हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध 64 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन को आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आवश्यक 615 हेक्टेयर भूमि को राज्य शासन द्वारा अर्जित कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिये जाने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया।
- रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित होने के उपरांत ए.टी.आर. जैसे बोइंग विमान की लैंडिंग हो सकेगी, जिससे रीवा क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा एवं पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा, इससे आम जनता को सीधे लाभ पहुँचेगा।
- मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुमोदन किया तथा विधेयक को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने की समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग को अधिकृत किया।
- सीमांकन के मामलों के निराकरण के लिये सक्षम अधिकारी तहसीलदार हैं। प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की संख्या सीमित होने और सीमांकन के आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिये मध्य प्रदेश भू-राजस्वसंहिता में संशोधन प्रस्तावित है। अब तहसीलदार द्वारा सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक के साथ-साथ कस्बा पटवारी की रिपोर्ट भी ली जा सकेगी।
- मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश के विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिये मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु स्वरोज़गार योजना वर्ष 2022-23 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- विभाग के द्वारा संचालित योजना 2 भागों में संचालित होगी। विभाग एवं अभिकरण के माध्यम से व्यक्तिगत प्रकरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्व-सहायता समूह होने पर 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रथम बार लिये गए ऋण 25 प्रतिशत या अधिकतम 20 हज़ार रुपए (व्यक्तिगत प्रकरण) एवं 2 लाख रुपए (स्व-सहायता समूह) अनुदान। ब्याज दर पर 6 प्रतिशत अनुदान।
- अभिकरण द्वारा संचालित योजना में आई.टी.आई. द्वारा प्रशिक्षित नवयुवकों को रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम ऋण एवं अभिकरण के माध्यम से अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- अधिकतम 2 लाख रुपए के व्यक्तिगत में प्रकरण स्वीकृत किये जाएंगे। प्रथम बार लिये गए ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं द्वितीय ऋण पर 20 प्रतिशत अनुदान। प्रथम एवं द्वितीय ऋण पर ब्याज पद पर 6 प्रतिशत अनुदान।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 की अनुसूची में उल्लेखित 5 अधिनियमों का निरसन किया गया है। इसके माध्यम से निम्न 5 अधिनियमों को निरसित किया जाना है, जो पूरी तरह से अप्रचलित, अनावश्यक और महत्त्वहीन हो चुके हैं।
- मध्य प्रदेश बोर्स्टल एक्ट 1928, मध्य भारत लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1949, मध्य प्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश अश्व रोग अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम 1976।
- मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश राज्य में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का राज्य संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया तथा विधानसभा में पुन: स्थापित करने से पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदया की पूर्व मंजूरी हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की गई।

मोहसा-बावई में औद्योगिक विकास के लिये भूमि आवंटित की गई

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में निर्णय लिया गया ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की भूमि विभिन्न उद्योगों के आवंटन के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया है-
- मोहासा-बाबई में 54 एकड़ क्षेत्रफल को भारत सरकार की योजनांतर्गत ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण हेतु आरक्षित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
- मोहासा-बाबई में आवंटन योग्य 686 एकड़ भूमि पर टैक्सटाईल, गारमेंट, खादय प्रसंस्करण एवं अन्य सेक्टर के उद्योगों हेतु भूमि आवंटन किये जाने हेतु अनुमति दी गई है।
- औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में प्रतिबद्ध निवेशकों को इकाई स्थापना हेतु विशिष्ट लोकेशन में औद्योगिक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मध्य प्रदेश राज्य औदयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2014 के अंतर्गत भू-आवंटन की ऑनलाईन पद्धति को शिथिल करते हुए, भूखंडों का आवंटन ऑफलाईन पद्धति से किये जाने का अनुमोदन किया गया है।
- इकाईयों को नियम अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, एमपीआईडीसी भोपाल में प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी को प्रेषित किया जाएगा।
- प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संबंधित इकाईयों को भू-आवंटन हेतु निर्णय लिया जाएगा।
- औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन के लिये टेक्सटाईल एवं गारमेंट सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग जैसे रोज़गारमूलक इकाईयाँ प्राथमिकता की श्रेणी में चिह्नित किया जाएगा।
- मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाईयों को प्रचलित औद्योगिक नीति अनुसार विदयुत टैरिफ एवं विद्युत शुल्क से संबंधित सुविधाओं को छोड़कर नीति के प्रावधानों अनुसार अन्य लाभ/ सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- मोहासा-बाबई में प्रस्तावित स्थापित इकाईयों को निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (CCIP) से पृथक् से भू-प्रब्याजी/ विकास शुल्क में अतिरिक्त छूट/रियायत संबंधी पात्रता प्राप्त करने की सुविधा नहीं होगी।
- इकाई को मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 अनुसार भूमि के मूल्य में छूट/रियायत प्राप्त किये जाने की पात्रता नहीं होगी अर्थात इकाई की भू-प्रब्याजी मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 अनुसार भूमि के वास्तविक मूल्य के समतुल्य होगी।
- भूखंड के आवंटन हेतु प्रब्याजी एवं विकास शुल्क की छूट के संदर्भ में कोई आदेश होने पर उक्त आदेश औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में प्रभावी नहीं होंगे।
- मोहासा-बाबई में प्रस्तावित/स्थापित इकाईयों से विद्युत प्रदाय संबंधी अनुबंध को मध्य प्रदेश विदयुत नियामक आयोग के निर्देशों एवं रेगुलेशन के अंतर्गत किया जाएगा।
- भोपाल, मंडीदीप एवं बुदनी में बड़ी टेक्सटाइल एवं गारमेंट इकाइयों की स्थापना होने से मोहासा-बावई औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल कंपनियों जैसे-बेस्ट कार्पोरेशन, इंडोरामा, महिमा फाइबर्स, वर्धमान आदि द्वारा भूमि की मांग की जा रही है।

मध्य प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 का अनुसमर्थन

चर्चा में क्यों?

13 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से संबंधित प्रथम नीति का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह नीति प्रदेश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सक्षम उद्यमिता को बढ़ावा देने, नई तकनीकी का उपयोग कर शासकीय सेवाओं को मजबूत करने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने और समावेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करने की पहल करेगी।

- इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं-
  - मध्य प्रदेश को देश में शीर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) गंतव्य के रूप में स्थान दिलाना।
  - मानव संसाधन, निवेश और ज्ञान आधारित श्रम शक्ति जैसे कारकों को सुदृढ़ करके वर्ष 2030 तक 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स' (अपने मौजूदा 13 वे रैंक से) में मध्य प्रदेश को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान दिलाना।
  - एक प्रभावी एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर मध्य प्रदेश को अनुसंधान प्रकाशन, नवउद्यम, स्टार्टअप, औद्योगिक डिजाइन संबंधी नवाचार और पेटेंट जैसे संकेतकों को सुदृढ़ कर प्रदेश में ज्ञान आधारित उत्पादन को बढ़ाने में मदद करना।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य के समग्र व्यय को बढ़ाना और राज्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - मध्य प्रदेश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार (जैसे कि 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार') प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना।
  - एसटीईएम (STEM) प्रयोगों और प्रतियोगिताओं के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध करके प्राथमिक स्तर से ही, विशेष रूप से छात्राओं के बीच एसटीईएम (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देकर स्नातक, परास्नातक और पीएचडी स्तर पर एसटीईएम पाठ्यक्रमों में नामांकन अनुपात को बढ़ाना।
  - वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन के लिये एक आदर्श ढाँचे को विकसित करना।
  - धरातल की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को बढ़ावा देना।
  - कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में निजी उद्यमों के प्रोत्साहन के लिये आवश्यक अनुसंधान, विकास और नवाचार अधोसंरचना का निर्माण करना।
  - नवीन प्रौद्योगिकियों पर आधारित सक्रिय, कुशल और पारदर्शी G2C और G2B प्रणालियाँ विकसित कर जन आवश्यकताओं का सटीक आँकलन कर घर पहुँच सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी सेमीकंडक्टर्स, आईओटी, ब्लॉकचौन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, एआई और एआर/वीआर जैसी नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में विश्व स्तरीय मानव संसाधन का सृजन कर कौशल संवर्धन के क्षेत्र में अग्रेषित होना।
  - शासकीय डोमेन में उपलब्ध विशाल डेटा भंडार का लाभ उठाकर, गोपनीयता संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक सर्वसुलभ सैंडबॉक्स वातावरण निर्मित कर डेटा आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये एक प्रभावी और उत्तरदायी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
  - नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, हस्तांतरण, अनुकूलन और उपयोग को सुगम बनाने के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।
- प्रसंगिक नवाचार और विज्ञान शिक्षा का बढ़ावा देने के लिये शीर्ष संस्थानों (जैस आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, एनआईटी, आईआईआईटी, एनआईडी, एनआईएफटी, एनएलएस) संस्थानों को मध्य प्रदेश के एक ज़िले को गोद लेकर उस ज़िले मे स्थानीय रूप से विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रारंभिक वित्त-पोषण मेंटरशिप, प्रशिक्षण और श्रेष्ठ प्रथाओं का लाभ उठाने में मदद करने हेतु अग्रणी संस्थाओं (जैसे आईटीआई, आईआईआईटी, आदि) में नवाचार समूहों, इन्क्यूबेटरों और एक्सेलेरटरों की स्थापना की जाएगी।

मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर से 5G नेटवर्क की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकालेश्वर और महाकाल लोक परिसर से राज्य में पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- रिलायंस जिओ द्वारा महाकालेश्वर और नवनिर्मित महाकाल लोक परिसर में इस 5G सेवा की शुरुआत की गई है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नेटवर्क और डिजिटल सुलभता के चलते राज्य अब तेजी से विकास करेगा और 5G सेवाओं की शुरुआत से राज्य के विकास को भी गति मिलेगी।
- रिलायंस जिओ द्वारा महाकालेश्वर और नवनिर्मित महाकाल लोक परिसर में शुरू की गई 5G सेवा पूर्णत: मुफ्त है और आम जनता और वहाँ जाने वाले सभी पर्यटकों के लिये फ्री उपलब्ध रहेगी।

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने लॉन्च किया मुक्ता ब्रांड घी

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित बुंदेलखंड की 18 हज़ार 500 से अधिक महिला डेयरी किसानों की दुग्ध उत्पादक कंपनी मुक्ता ने अपना ब्रांड 'मुक्ता घी' विधिवत लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी की यह बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश की 4 दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ प्रतिदिन 2 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन करती हैं, जिनमें अकेली मुक्ता कंपनी एक लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर रही है। कंपनी का वार्षिक टर्न-ओवर 65 करोड़ रुपए से अधिक है।
- इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एल.एम. बेलवाल ने कहा कि यह एक प्रेरणादायक स्टार्ट-अप है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रतीक है।
- मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 4 लाख 12 हज़ार स्व-सहायता समूह गठित हैं, जिनसे 46 लाख ग्रामीण महिलाओं का आजीविका संवर्धन किया जा रहा है।
- प्रदेश में 88 किसान उत्पादक कंपनियाँ भी बनाई गई हैं, जिनके एक लाख 79 हजार सदस्य प्रमुख रूप से कृषि आधारित गतिविधियाँ कर रहे हैं। इन कंपनियों का वर्ष 2022-23 में नवंबर माह तक 529 करोड़ रुपए टर्न ओवर हो चुका है। गत वर्ष अकेली मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी ने 65 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया, जिसमें 85 प्रतिशत बिक्री से आय का भुगतान सदस्यों को दूध के रूप में किया गया।
- कंपनी द्वारा प्रत्येक गाँव में दूध की खरीदी के लिये उन्नत स्व-चलित दूध संग्रहण प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें दूध बेचने वाले सदस्य दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जाँच स्वयं कर सकते हैं। उन्हें मुद्रित पावती पर्ची भी मिलती है और उनके मोबाइल पर बेचे गए दूध का पूरा विवरण आ जाता है।
- कंपनी का मोबाइल एप दूध के लेन-देन की जानकारी देता है। कंपनी पशुओं में दूध की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कृत्रिम गर्भाधान, खनिज मिश्रण, फर्टिलिटी कैंप, अवेयरनेस जैसे कार्य कर रही है।
- उल्लेखनीय है कि मुक्ता कंपनी ने इंडिया डेयरी अवार्ड-2021 में डेयरी एक्सटेंशन पुरस्कार भी प्राप्त किया है। कंपनी ने 4 साल की अल्प अवधि में यह सफलता पाई है। आगामी 2 वर्ष में प्रदेश में दुग्ध उत्पादक कंपनियों से 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य है।

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने लॉन्च किया मुक्ता ब्रांड घी

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित बुंदेलखंड की 18 हज़ार 500 से अधिक महिला डेयरी किसानों की दुग्ध उत्पादक कंपनी मुक्ता ने अपना ब्रांड 'मुक्ता घी' विधिवत लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी की यह बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश की 4 दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ प्रतिदिन 2 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन करती हैं, जिनमें अकेली मुक्ता कंपनी एक लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर रही है। कंपनी का वार्षिक टर्न-ओवर 65 करोड़ रुपए से अधिक है।

नोट :

- इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एल.एम. बेलवाल ने कहा कि यह एक प्रेरणादायक स्टार्ट-अप है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रतीक है।
- मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 4 लाख 12 हज़ार स्व-सहायता समूह गठित हैं, जिनसे 46 लाख ग्रामीण महिलाओं का आजीविका संवर्धन किया जा रहा है।
- प्रदेश में 88 किसान उत्पादक कंपनियाँ भी बनाई गई हैं, जिनके एक लाख 79 हजार सदस्य प्रमुख रूप से कृषि आधारित गतिविधियाँ कर रहे हैं। इन कंपनियों का वर्ष 2022-23 में नवंबर माह तक 529 करोड़ रुपए टर्न ओवर हो चुका है। गत वर्ष अकेली मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी ने 65 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया, जिसमें 85 प्रतिशत बिक्री से आय का भुगतान सदस्यों को दूध के रूप में किया गया।
- कंपनी द्वारा प्रत्येक गाँव में दूध की खरीदी के लिये उन्नत स्व-चलित दूध संग्रहण प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें दूध बेचने वाले सदस्य दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जाँच स्वयं कर सकते हैं। उन्हें मुद्रित पावती पर्ची भी मिलती है और उनके मोबाइल पर बेचे गए दूध का पूरा विवरण आ जाता है।
- कंपनी का मोबाइल एप दूध के लेन-देन की जानकारी देता है। कंपनी पशुओं में दूध की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कृत्रिम गर्भाधान, खनिज मिश्रण, फर्टिलिटी केंप, अवेयरनेस जैसे कार्य कर रही है।
- उल्लेखनीय है कि मुक्ता कंपनी ने इंडिया डेयरी अवार्ड-2021 में डेयरी एक्सटेंशन पुरस्कार भी प्राप्त किया है। कंपनी ने 4 साल की अल्प अवधि में यह सफलता पाई है। आगामी 2 वर्ष में प्रदेश में दुग्ध उत्पादक कंपनियों से 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सभी 31 हज़ार 425 आँगनवाड़ी भवनों में विद्युत संयोजन किये जाने की स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी आगनवाड़ी केंद्रों में विभागीय निर्मित, निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित होने वाले 31 हज़ार 425 भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिये विद्युत संयोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक तीन चरणों में विद्युत संयोजन का कार्य होगा। पहले वर्ष में 14 हज़ार 214, दूसरे वर्ष में 10 हज़ार 907 और तीसरे वर्ष में 6 हज़ार 304 आँगनवाड़ी भवन में विद्युत संयोजन किया जायेगा।
- यह कार्य शत-प्रतिशत राज्य मद से किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 79 करोड़ 7 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुसमर्थन किया गया और विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुचारु संचालन के लिये केंद्रीय सोसायटी में प्रशासक की सहायता के लिये 5 व्यक्तियों की समिति गठित किये जाने के प्रावधान का अनुसमर्थन किया गया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 का अनुमोदन और विधेयक को विधानसभा में पुर:स्थापित कर पारित कराने के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत करने का अनुसमर्थन किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा के क्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2017 के नियम-15 में संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने का निर्णय लिया। 'प्रतिज्ञान की शपथ' में सेवा के सदस्य के स्थान पर ज़िला न्यायाधीश शब्द प्रतिस्थापित किया।

नोट :

स्कूली शिक्षा में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित ईएफए (एजुकेशन फॉर ऑल) स्कूलों में प्रारंभ किये गए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'विषय की कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वी की पुस्तकों का विमोचन करते हुए बताया कि स्कूली शिक्षा में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रदेश में कुल 53 स्कूलों में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'विषय प्रारंभ किया गया है। इसे फिलहाल कक्षा 8वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों के लिये प्रारंभ किया गया है।
- राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इन स्कूलों में 40 आधुनिक कंप्यूटर्स की इंटरनेट युक्त प्रयोगशाला भी स्थापित की गई हैं।
- मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकी विषयों के समावेश एवं अनुप्रयोग पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जहाँ ईएफए (एजुकेशन फॉर ऑल) विद्यालयों में कक्षा आठवीं और नौवीं में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'की कुल 240 घंटों की क्लास के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। सर्वसुविधायुक्त कंप्यूटर लैब की उपलब्धता से इस विषय की पढ़ाई में विद्यार्थियों को सुगमता हो रही है।
- 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस'जैसी नवीनतम तकनीक के साथ भारत को विश्व के समक्ष खड़ा करने के लिये विद्यार्थियों को इसका रचनात्मक प्रयोग और मानव कल्याण की दिशा में उपयोग करना सिखाया जा रहा है, जिसमें यह पाठ्यक्रम अति उपयोगी साबित होगा।

मध्य प्रदेश पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने विधानसभा में सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया कि मध्य प्रदेश पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख सचिव सहकारिता ने बताया कि पैक्स के माध्यम से 16 हज़ार 452 उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है।
- विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। आईसीएमआईएस पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है।
- विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज योजना में वर्ष 2021-22 में खरीफ सीज़न के लगभग 18 लाख कृषक और रबी सीज़न के 14 लाख कृषक को 16 हज़ार 860 करोड़ रुपए के फसल ऋण से लाभान्वित किया गया है।
- वर्ष 2022-23 में खरीफ सीज़न के 19 लाख कृषक और रबी सीज़न में अब तक 7 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं। अब तक 14 हज़ार 699 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरण किया गया है। पीएम किसान योजना के सहकारी बैंकों के पात्र हितग्राहियों को 39 लाख 57 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए हैं।

6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

20 दिसंबर, 2022 को भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम के मार्शल आर्ट भवन में 310 महिला मुक्केबाज़ों के बीच मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- चैंपियनशिप में पहले दिन अलग-अलग वेट कैटेगरी के कुल 27 क्वालीफाइंग मुकाबले हुए। पहले दिन मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की अंजलि शर्मा ने 45-48 किग्रा. की मिनिमम वेट कैटेगरी में आंध्र प्रदेश की ज्योति गोरली को 5-0 से हराकर प्रिलिमिनरी राउंड क्वालीफाई किया। अकादमी की ही मंजू बामबोरिया ने 63-66 किग्रा. वेट कैटेगरी में अपना बाउट क्वालीफाई किया।
- तेलंगाना की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ निखत जरीन ने 48-50 किग्रा. फ्लाई वेट कैटेगरी में तमिलनाडु की एल. के. अभिनया को हराकर क्वालीफाई राउंड क्लियर किया। निखत ने आरएससी (रेफरी स्टॉप कॉन्टेक्ट्स) के ज़रिये ये बाउट जीता।
- 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में देश की एशियाई मुक्केबाज़ी की गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, विश्व जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निया लाथेर और सिमरनजीत कौर जैसी दिग्गज मुक्केबाज़ पंच बरसाती नज़र आएंगी।
- इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की 12 बॉक्सर्स अलग-अलग वेट कैटेगरी में अपने पावर का प्रदर्शन करेंगी।

स्टेट हैंडलूम एक्सपो में डिजाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को मिले पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा फैब्रिक्स ऑफ मध्य प्रदेश की थीम पर आयोजित डिजाइन काम्पटीशन के विजेताओं को भोपाल हाट बाज़ार, भोपाल में स्टेट हैंडलूम एक्सपो-2022 पुरस्कार वितरित किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल डॉ. रीनू यादव एवं मिसेज यूनिवर्स जॉय सुश्री अमृता त्रिपाठी ने स्टेट हैंडलूम एक्सपो-2022 के पुरस्कारों का वितरण किया।
- भोपाल ज़िले से एथनिक वियर श्रेणी में अमातुल्लाह बोहरा, अर्चना विश्वकर्मा एवं सलमा अंसारी तथा रेडी टू वियर श्रेणी में नंदिता नायर, फराह नदीम एवं मान्या यादव को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया।
- इसी प्रकार इंदौर ज़िले से एथनिक वियर श्रेणी में राखी गुप्ता, सीमा पारीक एवं समीक्षा नायक तथा रेडी टू वियर श्रेणी में दिव्या राठी, सौरवकांत श्रीवास्तव एवं गुलिका अग्रवाल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया।
- सभी विजेताओं को 'एक ज़िला-एक उत्पाद' योजना में चयनित सात ज़िलों के सात उत्पाद एवं प्रशस्ति-पत्र उपहार स्वरूप दिये गए।
- प्रदेश के हथकरघा, खादी एवं रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की पारंपरिक प्रक्रिया को सहेजने और उनके पीछे छुपी हुई समृद्ध निर्माण कला का प्रदेशवासियों को परिचय देने के उद्देश्य से डिजाइन प्रतियोगिता के अतिरिक्त हैंडलूम ऑन व्हील्स का भी आयोजन किया गया था।

लोक निर्माण विभाग में 'क्वालिटी कंट्रोल सेल' गठित

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये सचिव लोक निर्माण की अध्यक्षता में 'क्वालिटी कंट्रोल सेल' का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल सेल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ समय-सीमा में कार्य पूर्णता पर नज़र रखेगा। इसके अलावा समय-समय पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिये तकनीकी सर्कुलर भी जारी करेगा।
- प्रमुख सचिव ने बताया कि सेल में सचिव लोक निर्माण आर.के. मेहरा अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य अभियंता उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर बी.पी. बोरासी, अधीक्षण यंत्री सेतु मंडल एम.पी. सिंह, सहायक यंत्री सी.वी. तिवारी, सहायक यंत्री संजय कुलकर्णी और सलाहकार मंत्रालय रितेश जैन समिति सदस्य होंगे।

नोट :

संस्कृति विभाग के राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों की घोषणा

चर्चा में क्यों?

21 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने वर्ष 2021 के राज्य शिखर सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य शिखर सम्मान दिये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के संचालक अदिति कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा प्रति वर्ष कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा इन राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित किया गया है।
- राज्य शिखर सम्मान के लिये चयनित सभी कलाकार एवं साहित्यकारों को सम्मानस्वरूप एक-एक लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पटिका एवं शॉल-श्रीफल प्रदान किया जाता है।
- राज्य शिखर सम्मान के लिये चयनित कलाकार/साहित्यकार हैं-
  - हिन्दी साहित्य के लिये- डॉ. अश्विनी कुमार दुबे (इंदौर)
  - उर्दू साहित्य के लिये- डॉ. नरेंद्र वीरमणि (इंदौर)
  - संस्कृत साहित्य के लिये- भगवतीलाल राजपुरोहित (उज्जैन)
  - शास्त्रीय संगीत के लिये- पं. श्रीधर व्यास (उज्जैन)
  - शास्त्रीय नृत्य के लिये- डॉ. विजया शर्मा (भोपाल)
  - रूपंकर कलाओं के लिये- अनिल कुमार (भोपाल)
  - नाटक के लिये- प्रशांत खिरवड़कर (भोपाल)
  - दुर्लभ वाद्य वादन के लिये- मुन्ने खाँ (भोपाल)
  - जनजातीय एवं लोक कलाओं के लिये- सावनी बाई (डिंडोरी)
- राष्ट्रीय सम्मानों के लिये चयनित कलाकार/साहित्यकार हैं-
  - राष्ट्रीय कबीर सम्मान- डॉ. श्याम सुंदर दुबे (हटा) (3 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान- सदानंद गुप्त (गोरखपुर) (2 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय इकबाल सम्मान हैदराबाद के डॉ. सैयद तकी आब्दी को (2 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान- डॉ. श्रीराम परिहार (खंडवा) (2 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान- जनजाति कल्याण केंद्र महाकोशल (डिंडोरी) (2 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान- सुश्री रुक्मिणी विजय कुमार (हैदराबाद) (25 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान- रविशंकर श्रीवास्तव (भोपाल) (1 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान- सुश्री शिखा वार्ष्णेय (लंदन) (1 लाख रुपए),
  - राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान- डॉ. हाइंस वेर्नर वेसलर (डेनमार्क) (1 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान- जयंत विष्णु नार्लीकर (कोल्हापुर) (1 लाख रुपए)
  - राष्ट्रीय हिन्दी सेवा सम्मान- अजीत वड़नेरकर (भोपाल) (एक लाख रुपए)।

25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हुआ समापन

चर्चा में क्यों?

22 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के तलैया फील्ड मैदान में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें पुरूष वर्ग में गुजरात एवं महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल चैंपियन बना।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ 16 दिसंबर को किया गया था। इस दौरान पुरूष एवं बालिका वर्ग में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
- 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरूष वर्ग में गुजरात एवं हरियाणा के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें गुजरात विजेता और हरियाणा की टीम उपविजेता रही। कर्नाटक की टीम तीसरे एवं उत्तर प्रदेश की टीम चौथे स्थान पर रही।
- इसी प्रकार महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पश्चिम बंगाल विजेता और राजस्थान की टीम उपविजेता रही, जबकि गुजरात की टीम तृतीय व तमिलनाडु की टीम चतुर्थ स्थान पर रही।
- अलग-अलग वर्ग में विजेता टीम को 51 हज़ार रुपए और प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 हज़ार रुपए का पुरस्कार, गोल्ड मैडल एवं ट्राफी प्रदान की गई। उपविजेता टीम को 31 हज़ार रुपए एवं प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 हज़ार रुपए का पुरस्कार, सिल्वर मैडल प्रदान किया गया। तृतीय स्थान की टीम को 21 हज़ार रुपए व चतुर्थ स्थान की टीम को 11 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

मध्य प्रदेश ट्रांसको के लोड डिस्पेच सेंटर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

23 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) के जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर को उसके विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे, नवाचार करने, देश में सर्वप्रथम साइबर सिक्योरिटी मॉडल विकसित करने सहित अन्य मापदंडों में अग्रणी होने से देश के पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोड डिस्पेच सेंटर (भार प्रेषण केंद्र) उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रमुख बिंदु

- भारत के बिजली सेक्टर की राष्ट्रीय संस्था ग्रिड इंडिया से संबंधित फोरम ऑफ लोड डिस्पेचर एवं आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित नेशनल पावर सिस्टम कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश ट्रांसको की तरफ से मुख्य अभियंता स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर जबलपुर एस.एस. पटेल एवं अधीक्षण अभियंता आर.के. गुप्ता ने पुरस्कार ग्रहण किया।
- गौरतलब है कि उत्कृष्ट लोड डिस्पेच सेंटर की चयन प्रक्रिया में देश के 43 लोड डिस्पेच सेंटर्स ने हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को देश के पावर सेक्टर का यह बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रिड मापदंडों का पालन करने और पुरस्कार चयन की तीन चरणों की कठिन प्रक्रियाओं से गुज़रने के बाद मिला है।
- चयन प्रक्रिया के पहले चरण में 40 से अधिक मापदंड बिंदुओं पर वस्तुस्थिति के आधार पर मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और तेलंगाना प्रदेश चुने गए। दूसरे चरण में प्रेजेंटेशन एवं चारसदस्यीय जूरी द्वारा लिये गए मौखिक साक्षात्कार के आधार पर पहले चरण में चयनित तीनों स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर्स की परफॉर्मेंस परखी गई।
- आईआईटी के प्रोफेसर्स, पोसोको (ग्रिड इंडिया) के विश्वस्तरीय रिटायर्ड विशेषज्ञ और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नामी विशेषज्ञों की जूरी द्वारा तीसरे चरण की प्रक्रिया के बाद समग्र रूप से मध्य प्रदेश के राज्य लोड डिस्पेच सेंटर को इस पुरस्कार के लिये चुना गया।
- पुरस्कार के लिये पहले देश के सभी राज्य लोड डिस्पेच सेंटरों से आवेदन मँगाए गए। राज्य लोड डिस्पेच सेंटरों के बुनियादी ढाँचे, नवाचार में किये गए कार्यों का विवरण, पावर सेक्टर की चुनौतियों से निपटने के तरीके, साइबर सिक्योरिटी के लिये पालन की गई प्रक्रिया, ग्रिड मैनेजमेंट कार्मिकों को ट्रेनिंग और उनके वेलफेयर के लिये किये गए कार्य, अत्याधुनिक आईटी सिस्टम की उपलब्धता, रियल टाइम डाटा का संग्रहण, नवीनीकरण ऊर्जा के ग्रिड के साथ एकीकरण, आइसलेंडिंग स्कीम आदि बिंदुओं पर जानकारी दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने सीहोर ज़िले में किया सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सीहोर ज़िले के ग्राम सेमरी में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और 3 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सीहोर ज़िले के ग्राम सेमरी में लोकार्पित हुई रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना से पूरे क्षेत्र में सुख-समृद्धि आएगी। यह योजना शुरू होने से अब ग्राम बोरी, रतनपुर, सेमरी, डोंगरी और खनपुरा के 600 किसानों की 1084 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगेगी।
- मुख्यमंत्री ने परियोजना से शेष रहे 7 गाँवों की सिंचाई सुविधा के लिये 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा भी की।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस उद्वहन सिंचाई योजना से 40 फीट नीची नहर से पानी ऊपर लाया गया है। इसके अलावा 600 किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिये 9 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन खेतों में डाली गई है। हर 6 हेक्टेयर पर एमओएक्स बॉक्स लगाकर खेतों को सींचा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला: वन मंत्री डॉ. शाह ने वन मेले में वितरित किये पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

26 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के समापन कार्यक्रम में पुरस्कार वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

- वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने प्रदर्शनी के क्षेत्र में एम.पी.एम.एफ.पी. पार्क भोपाल को प्रथम, सामाजिक वानिकी को द्वितीय और मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को तृतीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड प्रदान की।
- वन मंत्री ने प्रधानमंत्री वन धन योजना में पूर्व छिंदवाड़ा वन धन केंद्र को प्रथम, पूर्व मंडला वन धन केंद्र को द्वितीय, उत्तर सिवनी वन धन केंद्र को तृतीय एवं दक्षिण पन्ना वन धन केंद्र और उमरिया वन धन केंद्र को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया।
- प्रदेश में संचालित विभिन्न ज़िला यूनियनों में से सीहोर ज़िला यूनियन को प्रथम, औब्दुलागंज यूनियन को द्वितीय, पश्चिम बैतूल ज़िला यूनियन को तृतीय और गुना एवं छतरपुर यूनियन को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।
- वन मंत्री डॉ. शाह ने मेले में शामिल हुई निजी संस्थाओं में से विशाल जवारिया, पचमढ़ी को प्रथम, त्रिशटा टी को द्वितीय और आदिवासी आयुर्वेदिक पचमढ़ी को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
- अन्य राज्यों की संस्थाओं में छत्तीसगढ़ राज्य (लघु वनोपज) को प्रथम, दीपू मिश्रा प्रतापगढ़ को द्वितीय, सुखदेव समत मेदनीपुर को तृतीय पुरस्कार से नवाज़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्टॉलों की श्रेणी में नेपाल को पुरस्कृत किया गया। राज्य बाँस मिशन एवं विंध्य हर्बल को विशेष पुरस्कार से नवाज़ा गया।
- शहद संग्रहण में सामुदायिक प्रयास के लिये पश्चिम बैतूल की नांदा समिति को विशेष सम्मान, नर्मदापुरम वन मंडल में स्थापित वन धन विकास केंद्र को महुआ का ब्रिटेन में सफल निर्यात करने और छिंदवाड़ा के मैनावाड़ी वन धन केंद्र के अंतर्गत 'वनभोज रसोई' को सफल सामुदायिक उपक्रम के विशेष सम्मान से नवाज़ा गया।
- गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 20 से 26 दिसंबर तक हुआ।

विक्रमोत्सव-2023

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में विक्रमोत्सव से संबंधित बैठक में बताया कि 18 फरवरी से 22 मार्च, 2023 की अवधि में उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2023 के विक्रमोत्सव के प्रथम दिवस पर दीप अर्पित करने के कार्यक्रम को वृहद् और गरिमामय बनाने के लिये प्रयास किये जाएँ, जिससे कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो।

- विक्रमोत्सव में महाशिवरात्रि से वर्ष प्रतिपदा तक भक्ति गायन, प्रदर्शनी, हस्तशिल्प व्यापार मेला, नाट्य प्रस्तुति, पुस्तक मेला, भजन मंडलियों की स्पर्द्धा, फिल्म समारोह, राष्ट्रीय वेद समागम, राष्ट्रीय युवा विज्ञान सम्मेलन, कवि सम्मेलन, प्रकाशन लोकार्पण, विभिन्न देशों के दलों द्वारा रामायण और महाभारत के प्रसंगों की प्रस्तुतियों के अलावा 'वृहत्तर भारत में संस्कृति साहित्य और पुरातत्त्व'विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी।
- विक्रमोत्सव के दौरान विक्रम पंचांग और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के लोकार्पण कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। शासन के विभिन्न विभाग, महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान संचालनालय, विक्रम विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, सांदिपनि वेद विद्यालय, अवंतिका विश्वविद्यालय, आचार्य वराहमिहिर वेधशाला सहित अन्य सामाजिक संगठन गतिविधियों में सहयोग करेंगे।

स्काई डाईविंग फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

28 दिसंबर, 2022 मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पर्यटन एवं संस्कृति द्वारा प्रदेश में स्काई डाईविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत 5 जनवरी, 2023 से उज्जैन के दताना एयरस्ट्रिप पर की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश में एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिये शुरू किये जा रहे इस स्काई डाईविंग फेस्टिवल का समापन 15 जनवरी को होगा।
- प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एवं जी-20 सम्मेलन के लिये प्रदेश में मौजूद रहने वाले अतिथि भी इस एडवेंचर गतिविधि का आनंद ले सकेंगे। इसका संचालन DGCA एवं USPA प्रमाणित संस्था 'स्काई-हाई इंडिया'द्वारा किया जा रहा है।
- शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल का पहला संस्करण सफल रहा था। सभी बुकिंग स्लॉट बुक हो चुके थे। इसी को देखते हुए अब दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है।
- इस दौरान उज्जैन में उच्च मानकों के साथ प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से रोमांच-प्रेमी स्काई डाईविंग का आनंद ले सकेंगे। वे 10 हज़ार फीट की ऊँचाई से महाकाल की नगरी को देखने का रोमांच भी प्राप्त कर सकेंगे।

पीबीडी और जीआईएस के लिये इंदौर में होम-स्टे योजना

चर्चा में क्यों ?

29 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इंदौर वासियों को अपने घर को होम-स्टे में बदल कर अतिरिक्त आय कमाने का सुनहरा दिया है, जिसके तहत प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिये इंदौर पहुँचने वाले अतिथियों के साथ पर्यटकों को भी होम-स्टे से आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इसके लिये मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड होम-स्टे पंजीयन के लिये 3 से 7 जनवरी 2023 तक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। अभियान में पंजीयन कराने वाले इंदौर के स्थानीय रहवासियों के आवेदन का फास्ट ट्रेक मोड पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिये इंदौर पहुँचने वाले प्रवासी भारतीयों को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं एवं खान-पान आदि का अनुभव प्रदान कराने, ठहरने के लिये स्वच्छ एवं किफायती स्थान उपलब्ध कराने और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये होम-स्टे पंजीयन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत इकाइयों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अतिथि आवास पूर्ण करने, इकाई में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा पंजीकृत इकाइयों को डिजिटल मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन के लिये तकनीकी सहायता, इकाई में कार्यरत मानव संसाधन की क्षमता वृद्धि, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेवल मार्ट एवं कार्य शालाओं में सहभागिता करने का अवसर प्रदान करता है।

नोट :

महानगरों की तर्ज पर तैयार होगा राहतगढ़ का अत्याधुनिक बस स्टैंड

चर्चा में क्यों ?

29 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश के सागर ज़िले के राहतगढ़ विकासखंड में 9 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक बस स्टैंड का भूमि-पूजन किया, जिसे महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसकी शुरूआत बस स्टैंड से की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने बताया कि सागर ज़िले के राहतगढ़ विकासखंड में करोड़ों रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के लिये यात्री प्रतीक्षालय, व्यवसाय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा, जो दुकानदार बस स्टैंड से विस्थापित होंगे, उनको प्राथमिकता के साथ व्यवसाय कॉम्प्लेक्स में स्थान दिया जाएगा। सर्व सुविधा युक्त रेस्ट हाउस भी अन्यत्र निर्मित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि राहतगढ़ विदिशा चौराहे से रेस्ट हाउस बस स्टैंड तक सड़क बनाई जा रही है, जिसमें अत्याधुनिक लाइटिंग की जा रही है और सड़क के दोनों ओर पौधा-रोपण भी किया जा रहा है।
- मंत्री ने समस्त राहतगढ़ वासियों को बताया कि राहतगढ़ में बन रहे बस स्टैंड का नाम सभी की सहमति से रखा जाएगा।

दृष्टि The Vision